International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 0.899
Vol.5 No.6 July-August 2018

शहरी आवास एवं भारतीय स्वच्छता मिशन

डॉ0 मधु प्रभा तिवारी
एसो0 प्रो0 अर्थशास्त्र
कालपी कॉलेज, (कालपी

शोध सारांश

भारत अभियान की शुरुआत राष्टपिता महात्मा गाँधी के जन्म दिवस वाले दिन 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी महात्मा गाँधी का हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसके चलते उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया था। गाँधी जी हमेशा स्वच्छता पर जोर देते थे। वो कहते थे स्वच्छता मे ही ईश्वर का निवास होता है। देश को आजादी दिलाने की वजह से उनका स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रह गया था। गाँधी जी देश के लोगो को देश में स्वच्छता बनाये रखने के लिए शिक्षा भी दिया करते थे।

ताकि हम एक स्वच्छ राष्ट का निर्माण कर सके और दूसरे देशो के लिए एक उदाहरण बन सके।

मुख्य शब्द : परिचय, उद्देश्य, प्रभाव।

सार

परिचय

देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का एक मिशन है इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने गाँधी जी की 150 वी वर्षगांठ, तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.96 लाख करोड़ रूपये की लागत से 1. 2 करोड़ नए शौचालय का निर्माण करना है, ताकि देश को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। सरकार ने यह लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक रखा है।

इस मिशन को सफल बनाने के लिए देश की कुछ बड़ी कंपनिया भी साथ आई है ये कंपनियां मिलकर देश में मई 2015 तक 3195 नए शौचालय का निर्माण करेगी इन कम्पनियो में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज महेंद्रा ग्रुप और रोटरी इंटरनेशनल सहित 14 कम्पनियाँ इस मिशन में हिस्सा लेंगी।

देश के अंदर हजारों लोग मानव मल साफ़ करने का कार्य करते है, तो आप समझ सकते है की देश के अंदर अभी कितने शौचालयों की जरूरत है ताकि देश को स्वच्छ बना सके।

आजादी के सात दशक बाद भी हमारे देश के हर घरों मे शौचालय नहीं है, आपको इस बात को बताते हुए बड़ा दुख होता है कि देश के अंदर अभी भी लोगो को खुले में शौच की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी आबादी अभी भी गावों में निवास करती है।

एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 72 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अभी सड़को के किनारे, खेतो में, झाड़ियों के पीछे , शौच करने के लिए मजबूर है। जिसकी वजह से देश में बच्चों के असमय मौत लोगो में संक्रमण, और नई नई बीमारियों का जन्म लेना और शौच के लिए सुनसान जगह पर गई लड़कियों का बलात्कार जैसी घटनायें बढ़ती जा रही है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ है जिसमे 55 प्रतिशत लोगो के पास शौचालय नहीं है। अधिकतर गावों और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगो के पास भी न तो शोचालय है और न ही पानी की सुविधा है, जिसके चलते शहरों में भी गंदगी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए इस समय देश के अंदर बड़े स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराने की आवश्यकता है।

इतिहास

स्वच्छ भारत आंदोलन की मुहिम आज तक स्वच्छता से संबंधित लिया गया एक बड़ा कदम है। इस अभियान को विश्वस्तर पर प्रसिद्ध करने के लिये तथा आम जनता को इसके प्रति जागरुक करने के लिये स्कूलों तथा कॉलेज के विद्यार्थीयों सहित लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारीयों ने इसके प्रारंभ होने के दिन इसमें भाग लिया। 1500 लोगों के मौजूदगी में 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने झंडा दिखाकर इस आंदोलन की शुरुआत की।

इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिये व्यापार, खेल और फिल्म उद्योग से जुड़े नौ प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामित किया। उन्होंने उन नौ व्यक्तियों से निवेदन भी किया कि वे और नौ व्यक्तियों को इस अभियान से जोड़ें और स्वच्छता के इस आंदोलन को देश के कोने–कोने में रहने वाले हर एक भारतीय तक इसे पहुचाऐ।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस मुहिम को चुनौती की तरह लेना चाहिये तथा व्यक्तिगत (पेड़ की शाखाओं की तरह) तौर पर दूसरे नौ लोगों को आमंत्रित करना चाहिये जिससे स्वच्छता का ये दृष्टीकोण 2019 तक पूरा हो जाए और इतिहास में हमेशा के लिये भारत एक स्वच्छ देश बने।

इस भारतीय अभियान से प्रेरणा लेकर 3 जनवरी 2015 को, इंडो–नेपाल डॉक्टर एशोसियन ने एक मुहिम की शुरुआत की जिसको "स्वच्छ भारत नेपाल– स्वच्छ भारत नेपाल अभियान" कहा गया। इसकी शुरुआत इंडो–नेपाल बार्डर क्षेत्र, सुनौली–बेलिहिया (भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, पवित्र शहर लुंबिनी,नेपाल) हुई।

भारत में स्वच्छता के दूसरे कार्यक्रम जैसे केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कायर्क्रम (सीआरएसपी) का प्रारंभ 1986 में पूरे देश में हुआ जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये स्वास्थयप्रद शौचालय बनाने पर केन्द्रित था। इसका उद्देश्य सूखे शौचालयों को अल्प लागत से तैयार स्वास्थयप्रद शौचालयों में बदलना, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के लिये शौचालयों का निर्माण करना तथा दूसरी सुविधाएँ जैसे हैंड पम्प, नहान–गृह, स्वास्थ्यप्रद, हाथों की सफाई आदि था। यह लक्ष्य था कि सभी उपलब्ध सुविधाएँ ठीक ढंग से ग्राम पंचायत द्वारा पोषित की जाएगी। गाँव की उचित सफाई व्यवस्था जैसे जल निकासी व्यवस्था, सोखने वाला गड्ढा, ठोस और द्रव अपशिष्ट का निपटान, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरुकता, सामाजिक, व्यक्तिगत, घरेलू और पर्यावरणीय साफ–सफाई व्यवस्था आदि की जागरुकता हो।

ग्रामीण साफ–सफाई कार्यक्रम का पुनर्निमाण करने के लिये भारतीय सरकार द्वारा 1999 में भारत में सफाई के पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की शुरुआत हुई। पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिये साफ–सफाई कार्यक्रम के तहत जून 2003 के महीने में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये एक प्रोत्साहन योजना थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2003 में लोगों को पूर्ण स्वच्छता की विस्तृत सूचना देने पर, पर्यावरण को साफ रखने के लिये साथ ही पंचायत, ब्लॉक, और जिलों द्वारा गाँव को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिये प्रारंभ की गई थी।

निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 2012 में हुई थी और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई। जबकि इसके पूर्व में भारतीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे है सभी सफाई–सफाई व्यवस्था और स्वच्छता कार्यक्रम वर्तमान 2014 के स्वच्छ भारत अभियान के जितना प्रभावकारी नहीं थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बुलावे पर ध्यान देते हुए कॉरपोरेट भारत ने भी इस अभियान को सफल बनाने के लिये उत्साह के साथ कदम आगे बढ़ाया।

अनिवार्य कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत स्वच्छता गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी कंपनीयों को जोड़ा जा रहा है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कानूनी जरुरत है। सीएसआर एक क्रियाविधी है जिसके द्वारा कंपनियाँ पूरे समाज के भले कार्यों में पूँजी लगाती है।

हाल ही में बड़े कॉरपोरेट घराने जैसे एलएनटी, डीएलएफ, वेदांता, भारती, टीसीएस, अंबुजा सीमेंट, टोयोटा किरलोस्कर, मारुती, टाटा मोटर्स, कोका कोला, डॉबर्र, आदित्य बिरला, अदानी, इंफोसिस, टीवीएस और कई दूसरों के पास निश्चित किये गये बजट स्वच्छ भारत अभियान के लिये है। एक अनुमान के मुताबिक कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा 1000 करोड़ की कीमत के कई स्वच्छता परियोजनाएँ पाइपलाइन में है। दूर–दराज़ के गाँवों में शौचालय बनाने सहित इन परियोजनाओं में व्यवहार में बदलाव लाने के लिये कार्यशाला चलाना, कचरा प्रबंधन तथा साफ पानी और दूसरी चीजों में साफ–सफाई क्रिया–कलाप आदि है।

स्वच्छ भारत अभियान के लिये एक बोली में कॉरपोरेट्स धन को आमंत्रित करना, अभी हाल ही में सरकार ने ये फैसला लिया कि इस स्कीम में कॉरपोरेट भागीदारी को सीएसआर खर्चे में गिनती होगी। और बाद में इसे स्पष्ट करने के लिये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी कंपनी अधिनियम के शेड्यूल 7 को संशोधित किया ये उल्लिखित करने के लिये कि स्वच्छ भारत कोष में योगदान सीएसआर के लिये योग्य होगा। इसलिये, ना केवल सरकरी और निजी शख्स बल्कि कॉरपोरेट क्षेत्रक भी भारत को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे है।

देश में रह रहे सभी नागरिकों के प्रयासों के द्वारा भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने के लिये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्पष्ट रुप से घोषित किया गया कि कोई भी इस कार्यक्रम में किसी भी समय सक्रिय रुप से भाग ले सकता है। उसे बस गंदी जगहों की एक तस्वीर लेनी है और इसके बाद उसे उस जगह की सफाई करने के बाद तस्वीर लेनी है और पहले और बाद की फोटो सोशल मीडिया वेबसाइटों जैसे फेसबुक, ट्वीटर आदि पर अपलोड कर देनी है जिससे इसी तरह का कार्य करने के लिये दूसरे आम लोग इससे परिचित और प्रेरित हो स्वच्छ भारत के दृष्टी को पूरा कर सके।

भारतीय जनता से भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की अपील के बाद ये भारत के लोगों द्वारा तेजी से शुरु हुआ। इस कार्यक्रम के आरंभ होने के दिन से ही लोग बहुत सक्रिय और प्रेरित हुए और इसको वैश्विक बनाने के लिये पहले और बाद की स्नैप लेकर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर अपलोड कर उसी तरह शुरु किया गया। नरेन्द्र मोदी द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी इस मुहिम को आगे बढ़ायेगा उसे सोशल मीडिया वेबसाइटों पर सरकरा द्वारा सराहा जायेगा। बॉलीवुड, टॉलीवुड, राजनीतिज्ञ, खेल, व्यापार उद्योग, आदि से जुड़े बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रितीक रोशन, सचिन तेंदूलकर, मृदुला सिन्हा जी, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, शशि थरुर, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, एम.वेंकैया नायडु, अमित शाह, सलमान खान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम और कई सारी हस्तियाँ अपने समयनुसार इस मुहीम से जुड़े तथा फेसबुक और ट्वीटर पर इससे जुड़ी तस्वीरें अपलोड की।

इसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्रों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा भी किया जा रहा है। दैनिक रुटीन कार्य और दूसरे व्यवसायिक गतिविधियों में लगे देश के युवा भी कार्यक्रम में भाग लेते है तथा इसी तरह का कार्य करते है। सभी क्रिया–कलाप प्रसिद्ध व्यक्तित्व, विद्यार्थी तथा देश के युवा द्वारा समर्थित होता है और आम जन को इसमें सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। अपने आस–पास के जगह को साफ और उत्तम करने के लिये हमें भारतीय होने के नाते अपने हाथों में झाड़ू लेने की जरुरत है।

ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने ग्रुप कार्यक्रम में भाग लिया था तो हम क्यूँ पीछे है ? हमें भी इसमें पूरी सक्रियता से भाग लेना चाहिये। इस अभियान को सफल अभियान बनाने के लिये कई स्वतंत्र एप्लिकेशन प्रोग्राम डेवलपर ने मोबाईल तकनीक का इस्तेमाल कर कई मोबाईल एप्लिकेशन बनाए। मीडिया ने भी अपने लेख और खबर प्रकाशन के द्वारा इस अभियान को बढ़ावा दिया। इस अभियान की ओर लोगों को टाईम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने लेख

"फेसबुक को देशी कंपनी ने हराया 'स्वच्छ एप्स रेस' में" से प्रेरित किया। दूसरा प्रकाशित लेख है–"ये भारतीय एप बदल सकता है कैसे लोग अपनी सरकार से बात करें"।

2019 तक 100 प्रतिशत खुले में शौचमुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये इस अभियान के तहत ठीक ढ़ंग से शौचालय बनाया जाना है जिसके लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी वास्तविक समय निगरानी की भी शुरुआत हुई है। लोगों को स्वच्छ भारत का महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाने के लिये एनआईटी राऊरकेला पीएचडी विद्यार्थीयों द्वारा स्वच्छ भारत पर एक लघु फिल्म बनाई गई है। हमें भी अपने हाथ इस मिशन के लिये जोड़ना चाहिये और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग समझना चाहिये। स्वच्छ भारत केवल एक का नहीं बल्कि सभी भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है।

स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। 2 अक्टूबर, 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान में शामिल होने के लिए आम जनता को आमंत्रित करने के कारण स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से लोगों में जिम्मेदारी की भावना आई और अब महात्मा गाँधी जी का 'स्वच्छ भारत' का सपना साकार होने लगा है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आए और सफाई के इस जन आंदोलन में शामिल हुए। सरकारी अधिकारियों से लेकर जवानों तक, बॉलीवुड अभिनेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक, सभी इस कार्य से जुड़े।

देश भर में लाखों लोग दिन–प्रतिदिन सरकारी विभागों, **NGO** और स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के स्वच्छता कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। सफ़ाई अभियानों के निरंतर आयोजनों के साथ–साथ देश भर में नाटकों और संगीत के माध्यम से सफ़ाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है, वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराना है। पर्यटन स्थलों, बाज़ारों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम पाँच साल की अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले 62,009 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की तरफ़ से 14623 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करना, मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन करना और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना हैं।

आम जनता के सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में जन–सहभागिता उसके सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु आवश्यक है। शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु जन–सहभागिता उनके सफल होने में अत्यावश्यक है–

1. प्रत्येक व्यक्ति को घरों से निकलने वाला कचरा कचरेदान में ही डालना चाहिए एवं नालियों की उचित रूप से सफाई करवानी चाहिए। इसके लिए स्वयं जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है।

2. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से योगदान देना चाहिए।

3. स्वच्छता एवं सुरक्षा के विषय पर बच्चों को स्कूल स्तर पर ही जागरूक करने की आवश्यकता है। स्कूलों में बच्चों द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु रैली निकाली जाती है, किन्तु उन्हें भी स्वच्छता के विषय में गंभीरता से जागरूक करने की आवश्यकता है।

4. कहीं भी असामाजिक तत्व दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए।

5. सरकार द्वारा पोलिथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, फिर भी आम जनता द्वारा पोलिथीन का उपयोग किया जा रहा है। पोलिथीन का उपयोग वातावरण के लिए हानिकारक है। पोलिथीन के नियमित उपयोग से बिसफेनोल रसायन शरीर में डायबिटीज़ व लीवर एंजाइम को असामान्य कर देता है। पोलिथीन कचरा जलाने से कार्बन–डाई–ऑक्साइड, कार्बन–मोनो–ऑक्साइड जैसी विषैली गैसें उत्सर्जित होती है जिनसे साँस, त्वचा आदि की बीमारियां होने की आशंका में वृद्धि हो जाती है। अतः सरकारी स्तर पर बनाए गए नियमों को जन–जागरूकता से ही अमल में लाया जा सकता है।

6. सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी करके भी शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया जा सकता है। इस प्रकार कोई भी नीति या नियम व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, किन्तु वह तभी सफल होता है जब व्यक्ति (आम जनता) द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित रूप से हो। हम जहाँ रहते हैं, उसे स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना सरकार के साथ–साथ जनता की भी ज़िम्मेदारी है, जिसे मिलजुल कर पूरा किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत क्षेत्रों की चुनौती

1. वर्तमान में शहरी क्षेत्र मुख्यतः 2 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे–

अ) ठोस और तरल अपशिष्ट का निपटान

ब) शहरी क्षेत्रों में सीवरेज का प्रबंधन।

2. उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट के निपटान में 3 प्रमुख घटक होते हैं, जैसे–

अ) अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण

ब) अपशिष्ट का स्थानांतरण

स) लैंडफिल क्षेत्र में उचित निपटानद्य अपशिष्ट संग्रह और लैंडफिल साइट तक उसके स्थानांतरण दोनों ही कार्यों में जनशक्ति के साथ–साथ एक कुशल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है।

3. विदित हो कि अधिकांश शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का निपटान करना मुख्य रूप से नगरपालिकाओं की ज़िम्मेदारी होती है। हालाँकि इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश की कई नगरपालिकाएँ अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु जनशक्ति, वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकी की कमी से जूझ रही हैं। अधिकांश नगरपालिकाएँ संसाधनों के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहती हैं।

4. दूसरी चुनौती शहरी क्षेत्रों में सीवरेज का प्रबंधन करना है। केवल शौचालय निर्माण से समस्या का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उचित सीवरेज नेटवर्क की भी आवश्यकता है, जैसे–

अ) अधिकांश भारतीय शहरी महानगर ऐसे सीवेज सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं जो दशकों पहले निर्मित किये गए थे और अभी भी सीवेज को नदियों या नहरों में ले जाने के पैटर्न का पालन करते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत का 70 प्रतिशत शहरी सीवेज अनुपचारित हैद्य दशकों पुराने होने के कारण कई सीवेजो में सुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

ब) कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भारतीयों के लिये वरदान से ज़्यादा अभिशाप हैं, क्योंकि आँकड़ों के अनुसार देश में मौजूद कुल एसटीपीएस में से 35 प्रतिशत से अधिक बेकार हैं।

स) चूँकि हम कई दशकों पुरानी सीवेज प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिये यह वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हैं।

5. सोक पिट जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है, शहरी इलाकों में जगह की कमी और बढ़ती जनसंख्या घनत्व के कारण काम नहीं कर सकती हैं।

6. यदि हम शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के लिये अपनाई गई रणनीति को देखें तो यह मुख्यतः व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों और आईईसी गतिविधियों के पर केंद्रित है।

7. ठोस कचरा प्रबंधन के लिये जो फंड निर्धारित किया गया है वह अपेक्षाकृत न्यूनतम है जो कि संपूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हैद्य इसी प्रकार सीवरेज नेटवर्क के लिये भी धन का जो प्रावधान किया गया है वह काफी कम है।

8. भारत के शहरी महानगरों और कस्बों में जगह की कमी है जिसके कारण अक्सर शहरी नगरपालिकाओं को शौचालय बनाने के लिये पर्याप्त स्थान खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

9. दिल्ली, पुणे और मुंबई जैसे महानगरों में कई अनधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों के कारण व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती है।

10. उल्लेखनीय है कि देश की शहरी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2040 तक भारत की शहरी आबादी वर्तमान 330 मिलियन से बढ़कर 830 मिलियन हो जाएगी।

11. आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की कुल लागत 62,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से एक चौथाई राशि का वहन केंद्र सरकार द्वारा और बाकी राज्य सरकारों एवं स्थानीय नगर निकायों द्वारा वहन किया जाना था। परंतु देश के स्थानीय नगर निकायों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और इसीलिये लागत का कुछ हिस्सा चुकाना भी उनके लिये मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण परियोजनाएँ रुक जाती हैं।

12. उदाहरण के लिये दिल्ली नगर निगम वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत से संबंधित किसी भी परियोजना पर काम शुरू नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके पास अपने योगदान की पूर्ति के लिये आवश्यक वित्त की कमी थी।

13. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा–निर्देशों में एक अन्य समस्या यह है कि इसके तहत निजी घरों में शौचालयों के निर्माण के लिये तो वित्त प्रदान किया जाता है, परंतु सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये किसी भी प्रकार की धन सहायता का उल्लेख नहीं है।

स्वच्छ भारत आगे की राह

1. ठोस अपशिष्ट और सीवर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। ताकि शहरों में मौजूद चुनौतियों को विशिष्ट रूप से संबोधित किया जा सके।

2. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को राज्य सरकारों से कचरे से निपटने में उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिये कहना चाहिये, जिससे प्रत्येक राज्य की क्षमता और कमियों को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जा सके।

3. कचरे के संग्रहण और उसके निपटान हेतु सरकारों को स्थानीय निकायों की क्षमता का ध्यान रखना चाहिये और आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिये।

4. नगरपालिकाओं को उनके राजस्व में वृद्धि करने हेतु अवसर दिया जा सकता है।

5. लैंडफिल क्षेत्रों के विकास के लिये भी अलग से धन आवंटित किया जाना चाहिये।

6. साथ ही देश के प्रमुख शहरों में अपशिष्ट संग्रहण और निपटान हेतु किये जा रहे सर्वोत्तम प्रयासों का अध्ययन और अनुकरण किया जाना चाहिये।

7. ध्यातव्य है कि जब तक हम सड़कों से कचरे को व्यवस्थित रूप से उठाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक स्वच्छता का कोई अर्थ नहीं होगा।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव

शहरी क्षेत्रों के स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य लगभग 104 करोड़ परिवारों को और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और साथ ही साथ 2.5 लाख समुदाय शौचालयों को प्रत्येक शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ उपलब्ध कराने का है।

आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है जहां व्यक्तिगत घरों के शौचालयों की उपलब्धता मुश्किल है बस स्टेशनों, पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि सहित निर्दिष्ट स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय बनाये जा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम में लगभग 4,401 कस्बों को 2019 तक पांच वर्षों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रमों की लागत ठोस कचरा प्रबंधन पर 7,366 करोड़ रुपये, सार्वजनिक जागरूकता पर 1,828 करोड़, सामुदायिक शौचालयों पर 655 करोड़ रुपये, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर 4,165 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

कार्यक्रम जिन्हें पूरा करने के लिए लक्षित किया गया है, वह हैं खुले में शौचालय को पूरी तरह से हटाना, गंदे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना, मैनुअल स्केवेन्गिंग को समाप्त करना, सार्वजनिक रूप से व्यवहारिक परिवर्तन लाने, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लाना आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने वाला मिशन है। इससे पहले निर्मल भारत अभियान (जिसे कुल स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है, टीएससी) 1999 में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को साफ करने के लिए स्थापित किया था, लेकिन अब इसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में पुनर्गठन किया गया है।

इस अभियान का लक्ष्य है कि 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों को खुले शौचालय से मुक्त किया जा सके, जिसके लिए देश में 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए लगभग एक लाख तीस हजार करोड़ रूपए लागत अनुमान लगाया गया।

यह कचरे को जैव उर्वरक और उपयोगी ऊर्जा रूपों में परिवर्तित करने की एक बड़ी योजना है। इस अभियान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की भागीदारी भी शामिल है।

निष्कर्ष

शहरी भारत में स्वच्छता की चुनौतियाँ कई मोर्चों पर ग्रामीण भारत से भिन्न हैं। स्थान, जनसांख्यिकी, व्यवहार और वित्त की समस्या शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में एक जैसी है, परंतु दोनों क्षेत्रों में इस समस्या की प्रकृति अलग–अलग है। अतः स्वच्छ भारत की समग्र सफलता सुनिश्चित करने के लिये दोनों क्षेत्रों की समस्याओं को अलग–अलग संबोधित किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. शुक्ल, डॉ. अरविन्द. (2016). स्वच्छ भारत अभियान चुनौतियाँ एव अवसर. प्रथम संस्करण, कानपूरः अराधना ब्रदर्स.
2. सिंह, डा. निशांत. (2004). जनसंपर्क और विज्ञापन. प्रथम संस्करण, नई दिल्लीः राधा पब्लिकेशन्स.
3. सुधीर, डॉ. सोनी. (2003). संचार शोध प्रविधियां. जयपुरः विश्वविधालय प्रकाशन
4. खान, डॉ. एम. व वर्मा, पी. (2016). स्वच्छ भारत अभियान का ग्राम पंचायत स्तरीय आलोचनात्मक विश्लेषण (ग्राम पंचायत बकैनिया जिला पीलीभीत के विशेष सन्दर्भ में).
5. गाँधी का आदर्श मोदी का संकल्प (2–8 अक्टूबर 2017) सुलभ स्वच्छ भारत, साप्ताहिक समाचार पत्रद्ध अंक 42, नई दिल्ली.
6. निष्ठा, अनुश्री (28 जून 2019). स्वच्छ भारत अभियान से कितना स्वस्थ हुआ भारत–कुछ डाटा कुछ अनुमान.
7. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय–एक पुस्तिका. (२०१७) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।